संख्या-117/2026/I/1467430/2026/71-1002(002)/2/2026

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनाँक 19 सितम्बर, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज परिसर में स्थापित प्रोफेसर, रीडर एवं लेक्चर आवासों के जीर्णोद्धार का कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/निर्माण/2026-27/145, दिनांक 15.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज परिसर में स्थापित प्रोफेसर, रीडर एवं लेक्चर आवासों के जीर्णोद्धार का कार्य हेतु टेण्डर लागत रू0 303.50 लाख के अनुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-15/2026/I/1216263/2026/71-1002(002)/2/2026, दिनांक 27.01.2026 द्वारा मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज परिसर में स्थापित प्रोफेसर, रीडर एवं लेक्चर आवासों के जीर्णोद्धार का कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 306.02 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज परिसर में स्थापित प्रोफेसर, रीडर एवं लेक्चर आवासों के जीर्णोद्धार का कार्य हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 27.01.2026 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 306.02 लाख को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/15, दिनांक 17.05.2023 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में **टेण्डर लागत के अनुसार रू0 303.50 लाख (रू0 तीन करोड़ तीन लाख पचास हजार मात्र)** की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है -

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. प्रश्नगत परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/15, दिनांक 17.05.2023, 19.05.2023 सपठित शासनादेश संख्या-5/2026/ए-2-आई/1365672/2026, दिनांक 18.06.2026 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में विहित प्रक्रिया का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायेगी।
3. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. यदि प्रश्नगत परियोजना में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज/कार्यदायी संस्था स्वंय उत्तरदायी होंगे।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित कर लेंगे।
6. परियोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-15/2026/I/1216263/2026/71-1002(002)/2/2026, दिनांक 27.01.2026 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।